



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

झारखंड

अगस्त

(संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड	3
➤ दिल्ली और देवघर के बीच सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ	3
➤ विश्व स्तनपान सप्ताह-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ	3
➤ झारखंड जनजातीय महोत्सव-2022 के प्रतीक चिह्न का अनावरण	4
➤ झारखंड जनजातीय महोत्सव-2022	4
➤ मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया	5
➤ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव को मंजूरी	5
➤ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को मिला सुरक्षा और स्थिरता श्रेणी में कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22	6
➤ झारखंड के निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता होगी रद्द	7
➤ एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत के सुझाव हेतु उप-समिति के गठन की स्वीकृति	7
➤ झारखंड सरकार तथा FSDO ब्रिटिश उच्चायोग के बीच एमओयू	7
➤ तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु 'क्रियान्वयन निर्देशिका' का विमोचन	8
➤ झारखंड के दो साहित्यकारों को साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा	9
➤ झारखंड की शिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित	9
➤ सीसीएल और मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन	10

झारखंड

दिल्ली और देवघर के बीच सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

30 जुलाई, 2022 को नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (जनरल) डॉक्टर वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने दिल्ली और देवघर के बीच इंडिगो एयरलाइन की सीधी उड़ान सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस नई उड़ान सेवा के साथ, देवघर से दैनिक प्रस्थान करने वाली उड़ानों की कुल संख्या 11 हो जाएगी। इससे बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों को निर्बाध आवाजाही में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे झारखंड में पर्यटन बढ़ेगा।
- गौरतलब है कि देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन इसी साल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 655 एकड़ में फैले देवघर हवाई अड्डे का निर्माण 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके तैयार होने से यह राँची के बाद झारखंड का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है।
- नागरिक विमानन मंत्री ने कहा कि झारखंड में 3 और हवाई अड्डों - बोकारो, जमशेदपुर तथा दुमका में बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे झारखंड में कुल हवाई अड्डों की संख्या 5 हो जाएगी।
- उन्होंने कहा कि झारखंड को जोड़ने वाले 14 नए मार्गों की घोषणा की गई है, जिनमें से 2 मार्ग - देवघर-कोलकाता और दिल्ली-देवघर पर काम शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में देवघर को राँची तथा पटना से और दुमका को राँची तथा कोलकाता से जोड़ा जाएगा। बोकारो हवाई अड्डा तैयार होने के बाद पटना और कोलकाता से जुड़ जाएगा।
- 'उड़ान' योजना के अंतर्गत 425 मार्ग और 68 हवाई अड्डा, हेलीपोर्ट, जल एरोड्रम का संचालन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 90 हजार से अधिक उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं।
- नागरिक विमानन मंत्रालय ने पिछले 8 वर्षों में 66 हवाई अड्डों का निर्माण किया है। इससे पहले वर्ष 2014 में हवाई अड्डों की संख्या केवल 74 थी। 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिसमें अगले 5 वर्षों में जल एरोड्रम और हेलीपोर्ट शामिल हैं।

विश्व स्तनपान सप्ताह-2022 का राज्यस्तरीय शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2022 को झारखंड की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने डोरंडा के पलाश सभागार में 'विश्व स्तनपान सप्ताह' के शुभारंभ पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 1 से 7 अगस्त तक चलेगी।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री ने 7 बच्चों को अन्नप्राशन कराया एवं कार्यक्रम से संबंधित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- विश्व स्तनपान सप्ताह-2022 की थीम 'स्तनपान को बढ़ावा और शिक्षा एवं सहयोग' है।
- मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री माताओं के बीच यह संदेश प्रसारित किया जाएगा, कि जो महिलाएँ बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाया जाए। यह दूध बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत उपयोगी है।

- उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक करना है कि माँ, अपने बच्चे को पहले 6 महीने में अपने दूध के अलावा कोई आहार न दें उसमें ही बच्चे के लिये जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार सही मात्रा और सही पोषक तत्व के साथ देना आवश्यक है। साथ ही 2 साल तक स्तनपान के साथ पोषक आहार देना चाहिये, जिससे बच्चे स्वस्थ रह सकें।
- जोबा मांझी ने कहा कि एनीमिया मुक्त, कुपोषण मुक्त समाज का निर्माण हो सके, इसके लिये लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। जागरूक होने से ही बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी एवं स्वस्थ बच्चों से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा।
- उन्होंने कहा कि किशोरियों को भी सही दिशा देने का काम करना है। बालिकाओं को स्वस्थ रखने, उनको एनीमिया से मुक्त कराने एवं उनकी सही समय पर शादी हो एवं परिपक्व शरीर में वे गर्भधारण करें, इसकी शिक्षा देना आवश्यक है।

झारखंड जनजातीय महोत्सव-2022 के प्रतीक चिह्न का अनावरण

चर्चा में क्यों ?

4 अगस्त, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 9 एवं 10 अगस्त, 2022 को राँची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले 'झारखंड जनजातीय महोत्सव-2022' के प्रतीक चिह्न का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार राँची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 'झारखंड जनजातीय महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है।
- इस समारोह में उत्तर-पूर्व (North-East) के कलाकार भाग लेंगे। इस समारोह में जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानवशास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी, कला एवं संगीत, परिधान, फैशन शो, खान-पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मिजोरम समेत अन्य जनजातीय बहुल राज्य के कलाकारों को भाग लेने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया है।
- कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह 9 अगस्त, 2022 को होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद शिवू सोरेन होंगे, जबकि 10 अगस्त को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। महोत्सव की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।
- इस दौरान मोरहाबादी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य-व्यंजन, कला एवं शिल्प की प्रदर्शनी आयोजित होगी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेमिनार और पैनल चर्चा मोरहाबादी हॉकी मैदान में संपन्न होगी।

झारखंड जनजातीय महोत्सव-2022

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो तथा राज्यसभा सांसद शिवू सोरेन ने झारखंड की राजधानी राँची के मोरहाबादी में दोदिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव-2022 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस जनजातीय महोत्सव-2022 में समृद्ध जनजातीय जीवन दर्शन की झलकियाँ दर्शाई गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों और जानवरों को बचाना है तो आदिवासियों को बचाएँ। जमीन, संस्कृति और भाषा आदिवासियों की पहचान निर्धारित करती हैं। विकास की उस नई परिभाषा से उनके अस्तित्व को खतरा होता है, जिसमें इमारतों और कारखानों को स्थापित करने के लिये जंगलों को काटना शामिल है।
- झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजने हेतु 'मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना' शुरू की गई है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये ऋण लेने के इच्छुक छात्रों हेतु जल्द ही 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना' शुरू की जाएगी। इसके अलावा एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना पर काम चल रहा है।

- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी उत्सव का आयोजन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार से इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आदिवासी परिवार में किसी की भी शादी के अवसर पर एवं मृत्यु होने पर उन्हें 100 किग्रा. चावल और 10 किग्रा. दाल दी जाएगी, इससे सामूहिक भोज के लिये अब उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं अन्य पदकों से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने मुरारी लाल मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), राँची एवं हवलदार महेंद्र प्रसाद, (विशेष शाखा), राँची को विशिष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
- शहीद, सहायक अवर निरीक्षक बनूआ उराँव, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार रजक, समादेष्टा (सीआरपीएफ), कुणाल को वीरता के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक/पुलिस पदक प्रदान किया गया।
- पुलिस उपाधीक्षक रांची/पुलिस उपाधीक्षक मुसाबनी चंद्रशेखर आजाद, पुलिस निरीक्षक श्याम किशोर महतो को अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृहमंत्री पदक प्रदान किया गया।
- अवर निरीक्षक तोवियस तोपनो, अवर निरीक्षक चंद्रभूषण सिंह, सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार राम, सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार यादव, सहायक अवर निरीक्षक मनींद्र कुमार, हवलदार संजय कुमार श्रेष्ठ, हवलदार धर्मेन्द्र कुमार, हवलदार विनय मांझी, हवलदार अजीत कुमार, हवलदार संजय कुमार यादव, हवलदार मुमताज खां, चालक आरक्षी राघवेंद्र नारायण चौबे तथा पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार राम को सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक प्रदान किया गया।
- इसी प्रकार पुलिस निरीक्षक हुलास पूर्ति, पुलिस निरीक्षक देवकी सागा, पुलिस अवर निरीक्षक पंकज उराँव, सहायक अवर निरीक्षक राजीव रंजन, सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सोमनाथ पांड्या, हवलदार बालेश्वर यादव हवलदार प्रदुमन गुप्ता, हवलदार जितेंद्र कुमार सिंह और हवलदार अरुण कुमार सिंह को सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक किसी भी पुलिस अधिकारी को राष्ट्र के लिये की जाने वाली उसकी सेवा के लिये दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से हजाराँ आदिवासियों का 30 वर्षों का संघर्ष समाप्त होगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 1964 में शुरू हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1999 में अवधि विस्तार किया गया था।
- नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार जिला के करीब 39 राजस्व ग्रामों द्वारा आमसभा के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित जनता द्वारा बताया गया था कि लातेहार व गुमला जिला पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पेसा एक्ट 1996 लागू है, जिसके तहत ग्रामसभा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

- इसी के तहत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित इलाके के ग्राम प्रधानों ने प्रभावित जनता की मांग पर ग्रामसभा का आयोजन कर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिये गाँव की सीमा के अंदर की जमीन सेना के फायरिंग अभ्यास हेतु उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया था। साथ ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को आगे और विस्तार न कर विधिवत् अधिसूचना प्रकाशित कर परियोजना को रद्द करने का अनुरोध किया था।
- गौरतलब है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से प्रभावित जनता द्वारा पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द करने हेतु विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा था। वर्तमान में भी प्रत्येक वर्ष की भाँति नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में 22-23 मार्च को विरोध-प्रदर्शन किया गया था।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को मिला सुरक्षा और स्थिरता श्रेणी में कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22

चर्चा में क्यों ?

18 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की झारखंड स्थित सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को 2021-22 के कोयला मंत्री पुरस्कार में सुरक्षा श्रेणी में द्वितीय और स्थिरता श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न श्रेणियों में कोयला मंत्री पुरस्कार, 2021-22 प्रदान किये।
- प्रह्लाद जोशी ने कोयला सचिव अनिल कुमार जैन और सीआईएल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की उपस्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के सीएमडी पी. एम. प्रसाद को ट्रॉफी प्रदान की।
- पिछले वर्ष पहली बार शुरू किये गए ये पुरस्कार तीन श्रेणियों- सुरक्षा (safety), उत्पादन एवं उत्पादकता (production & productivity) और निरंतरता (sustainability) में प्रदान किये गए थे।
- इन पुरस्कारों के दायरे में विस्तार करते हुए इस वर्ष गुणवत्ता (quality) और ईआरपी कार्यान्वयन (ERP implementation) की दो नई अतिरिक्त श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं। एक अन्य पहलू के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के महाप्रबंधकों (General Managers) को भी इस वर्ष चार उप-श्रेणियों में सम्मानित किया गया।
- पाँच श्रेणियों में दिये गए पुरस्कारों में से महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने तीन श्रेणियों, अर्थात् 'सुरक्षा', 'उत्पादन एवं उत्पादकता' और 'गुणवत्ता' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। 'निरंतरता' श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) को मिला, वहीं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने 'ईआरपी के कार्यान्वयन' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- गौरतलब है कि सीसीएल की स्थापना (सर्वप्रथम एनसीडीसी लिमिटेड) 1 नवंबर, 1975 को सीआईएल की पाँच सहायक कंपनियों में से एक सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड वर्ष 2007 से कैटेगरी 1 मिनीरल कंपनी है।
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने स्थापना के बाद से पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 68.8 मिलियन टन (एमटी) का उच्चतम उत्पादन और 71.8 मिलियन टन (एमटी) का प्रेषण दर्ज किया है।
- उल्लेखनीय है कि कोल इंडिया लिमिटेड कोयला हेतु देश की प्रथम नियंत्रक कंपनी है। शुरुआत में इसकी पाँच सहायक कंपनियाँ थीं, जबकि अभी सीआईएल की आठ सहायक कंपनियाँ हैं।
- कोल इंडिया लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम नवंबर, 1975 को अस्तित्व में आया। अपनी स्थापना के वर्ष में 79 मिलियन टन (एमटी) का साधारण उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड आज (11 अगस्त, 2022 तक) 224 मिलियन टन (एमटी) के उत्पादन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक तथा 2,48,550 (1 अप्रैल, 2022 के अनुसार) की जनशक्ति के साथ सबसे बड़ी कॉर्पोरेट नियोक्ता में से एक है।
- भारत के आठ राज्यों में फैली सीआईएल, अपनी अनुषंगी कंपनियों के 84 खनन क्षेत्रों में माध्यम से प्रचालनरत है। कोल इंडिया लिमिटेड की 318 खदानें हैं (1 अप्रैल, 2022 के अनुसार), जिनमें से 141 भूमिगत, 158 खुली खदानें और 19 मिश्रित खदानें हैं। सीआईएल के 21 प्रशिक्षण संस्थान और 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी हैं।

झारखंड के निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता होगी रद्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने यूजीसी गाइडलाइन तथा राज्य सरकार की गाइडलाइन की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने का आदेश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को दिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल रमेश बैस ने जाँच के क्रम में 15 दिनों में मांगी गई रिपोर्ट नहीं देने वाले निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही जाँच रिपोर्ट के आधार पर उन निजी विश्वविद्यालयों की भी मान्यता रद्द करने को कहा है जो निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते।
- गौरतलब है कि राज्यपाल ने जून के अंतिम सप्ताह में ही उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दो माह में सभी निजी विश्वविद्यालयों की जाँच के आदेश विभाग को दिये थे।
- विभाग की ओर से कमेटी के अलावा चार उप-समितियाँ गठित किये जाने तथा जाँच के लिये 16 निजी विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट मांगे जाने की जानकारी दी गई। इस पर राज्यपाल ने 15 दिनों में रिपोर्ट नहीं देने वाले विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये।
- यदि कोई विश्वविद्यालय रिपोर्ट नहीं देता है तथा जाँच में सहयोग नहीं करता है तो विश्वविद्यालय के संचालक से स्पष्टीकरण मांगकर मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
- उल्लेखनीय है कि निजी विश्वविद्यालयों को इस शर्त पर मान्यता दी गई थी कि वे दो वर्ष में आवश्यक जमीन तथा तीन वर्ष में आधारभूत संरचना का निर्माण कर लेंगे। कई विश्वविद्यालयों ने निर्धारित अवधि के बाद भी इन शर्तों को पूरा नहीं किया। निजी विश्वविद्यालयों के लिये पाँच साल में नैक से एक्कीडिशन प्राप्त करना तथा प्रत्येक वर्ष आडिट कराना भी अनिवार्य है। इन सभी की जाँच हो रही है।

एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत के सुझाव हेतु उप-समिति के गठन की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनु.-2) के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार-विमर्श कर सुझाव देने के लिये उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिये एक उप-समिति का गठन किया जाएगा।
- यह उच्चस्तरीय उप-समिति झारखंड में एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नज़र रखते हुए विचार-विमर्श कर अपना सुझाव राज्य सरकार को देगी।

झारखंड सरकार तथा FSDO ब्रिटिश उच्चायोग के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2022 को झारखंड सरकार एवं विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के बीच एमओयू तथा 'शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति 2023' (Chevening Marang Gomke Jaipal Singh Munda Overseas Scholarship 2023) का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस (Alex Ellis) की मौजूदगी में यह एमओयू संपन्न हुआ। साझा एमओयू के अंतर्गत अधिकतम पाँच छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

- गौरतलब है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब किसी राज्य सरकार के साथ साझा पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर एमओयू किया गया है।
- झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को झारखंड सरकार एवं ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा 'शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति' प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री के प्रयास से ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अधिकतम पांच युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 'मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना' का दायरा बढ़ाते हुए 'शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना' शुरू की गई है।
- इससे पूर्व तक झारखंड सरकार द्वारा 'मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना' के जरिये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थेन आयरलैंड के चयनित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के चयनित पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। अब अन्य वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
- इस एमओयू के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये 'शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना' हेतु झारखंड के अधिकतम 5 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित पाँच युवाओं की पढ़ाई का संपूर्ण व्यय झारखंड सरकार एवं विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग, (एफसीडीओ) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। एमओयू के तहत सभी भुगतान भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश के आलोक में होगा।
- गौरतलब है कि 'मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना' के तहत पूर्व में अधिकतम 10 युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब अधिकतम 25 युवाओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- झारखंड के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10, अनुसूचित जाति के अधिकतम 05, अल्पसंख्यक के अधिकतम 03 एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 7 प्रतिभावान युवाओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थेन आयरलैंड में स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स/एम.फिल. हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से सौ साल पहले झारखंड से एक ट्राइबल युवा जयपाल सिंह मुंडा जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला था। उन्होंने पढ़ने के साथ-साथ हॉकी में ऑक्सफोर्ड ब्लूज टीम की कप्तानी भी की। यही कारण है कि आज लोग उन्हें मरांग गोमके के नाम से जानते हैं। राज्य, देश और दुनिया में जयपाल सिंह मुंडा की अलग पहचान रही है।

तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु 'क्रियान्वयन निर्देशिका' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को एमडीआई भवन सभागार, धुर्वा में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु 'क्रियान्वयन निर्देशिका' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह 'क्रियान्वयन निर्देशिका' स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीडस) के द्वारा तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (टीओएफईआई) की गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु बनाई गई है।
- स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तंबाकू के सेवन से झारखंड के लोगों को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी कारण सरकार ने राजस्व के नुकसान की परवाह किये बगैर लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा है और तंबाकू को राज्य में प्रतिबंधित किया है।
- फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सरकार ने 11 नामजद तंबाकू पदार्थों को राज्य में प्रतिबंधित किया है। तंबाकू उन्मूलन अभियान को सख्ती के साथ लागू किया है। डब्ल्यूएचओ ने भी झारखंड में तंबाकू उन्मूलन अभियान के कार्य को प्रोत्साहित, सम्मानित और पुरस्कृत भी किया है।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों को तंबाकू सेवन से मुक्ति हेतु कई प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में किसी तरह के तंबाकू की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह रोक है। कोटपा कानून लागू है, जिसमें सजा के प्रावधान हैं। तंबाकू उन्मूलन अभियान से पहले झारखंड में 50 प्रतिशत लोग तंबाकू का सेवन करते थे, परंतु अब यह घट कर 9 प्रतिशत पर आ गया है।

- दीपक मिश्रा एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीड्स, नई दिल्ली ने तंबाकू के दुष्परिणामों, कानून में तंबाकू की खरीद-बिक्री के बारे में इसके सजा के प्रावधान से संबंधित जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी।
- उन्होंने बताया कि भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख लोगों की मौत होती है। झारखंड में 38.9 प्रतिशत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसमें से 34.5 प्रतिशत लोग चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-19 के अनुसार झारखंड में 13.15 वर्ष के 5.1 प्रतिशत बच्चे/अवयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं।

झारखंड के दो साहित्यकारों को साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं के लेखक-लेखिकाओं को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 और 23 भाषाओं के लेखक-लेखिकाओं को युवा साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की। इसमें झारखंड के दो साहित्यकार मिहिर वत्स और साल्गे हांसदा भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में लेखक-लेखिकाओं का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 व साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिये अनुमोदन किया गया।
- अकादमी ने कुल 22 भाषाओं के लेखक-लेखिकाओं को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिये जाने की घोषणा की, जबकि 23 भाषाओं के लेखक-लेखिकाओं को युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
- झारखंड के हजारीबाग जिले के मिहिर वत्स को उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई किताब 'टेल्स ऑफ हजारीबाग- एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटानागपुर प्लेटो'(Tales of Hazaribagh- An intimate Exploration of Chhotanagpur Plateau) के लिये युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया है। इसमें हजारीबाग पठारी क्षेत्र का यात्रा संस्मरण है।
- वहीं जमशेदपुर जिले के साल्गे हांसदा को उनकी द्वारा लिखी गई संथाली उपन्यास 'जनम दिसोम उजारोग काना'के लिये युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया है।
- अकादमी के सचिव ने बताया कि बाल साहित्य पुरस्कार की श्रेणी में पंजाबी भाषा में इस वर्ष पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, जबकि संथाली भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं युवा पुरस्कार की श्रेणी में मराठी में बाद में विजेता का ऐलान किया जाएगा।
- पुरस्कार के लिये चयनित लेखकों को पुरस्कारस्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक तथा 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

झारखंड की शिप्रा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिये चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की। इसमें झारखंड की शिप्रा मिश्रा का नाम भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार के तौर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को 50 हजार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा।
- पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनिवर्सिटी प्लस टू हाईस्कूल, कदमा की विज्ञान शिक्षिका शिप्रा मिश्रा झारखंड से एकमात्र शिक्षक हैं, जिनके नाम पर पुरस्कार के लिये शिक्षा मंत्रालय ने अंतिम मुहर लगाई। हालाँकि राज्य से कुल तीन शिक्षकों के नाम इस पुरस्कार के लिये भेजे गए थे।

- शिप्रा मिश्रा मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले से है। उन्होंने स्कूल को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में शिक्षिका का अहम योगदान है। वे स्कूल में छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने में लगातार अपने स्तर से कार्य करती रही हैं।
- शिप्रा की एक छात्रा नेहा सरदार का स्मार्ट विलेज के मॉडल ने विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर पुरस्कार जीता था। हाल ही में आईएसएम, धनबाद में आयोजित प्रतियोगिता में सरकारी स्कूलों की श्रेणी में टाटा वर्कर्स यूनिजन हाई स्कूल के छात्रों द्वारा बनाए गए ऑटोमेटिक क्लीन टॉयलेट (Automatic Clean Toilet) के प्रोजेक्ट को ओवरऑल श्रेणी के पुरस्कार के लिये चयनित किया गया था।
- शिप्रा मिश्रा को अब तक कई अवार्ड मिल चुके हैं। रोटरी क्लब की ओर से वर्ष 2017 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान, इनर व्हील क्लब की ओर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान, वर्ष 2019 में राज्य स्तर का शिक्षक पुरस्कार तथा 2020 में एनएमएल द्वारा बेस्ट साइंस टीचर्स अवार्ड मिल चुका है।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीन स्तरीय चयन प्रक्रिया के जरिए पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

सीसीएल और मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2022 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने राँची में एमडीओ मोड के माध्यम से पिपरवार भूमिगत खानों के संचालन के लिये मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से जीएम (पिपरवार), सीबी सहाय ने और निदेशक तकनीकी, मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कल्याण कुमार हजारा ने अपनी कंपनी की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- यह कोल इंडिया लिमिटेड की पहली भूमिगत खदान होगी जिसका संचालन एमडीओ मॉडल द्वारा किया जाएगा।
- इस परियोजना के चालू होने पर इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 0.87 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी।
- यह परियोजना यह सुनिश्चित करने के लिये अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करेगी कि खनन गतिविधियों से क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र बाधित न हो। इस परियोजना का पूंजीगत परिव्यय 1889.04 करोड़ रुपए है। खदानें 14 वर्षों तक चालू रहेंगी और पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिये पर्यावरण हितैषी विस्फोट मुक्त खनन किया जाएगा।
- एमडीओ मोड में, ठेकेदार पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी प्राप्त करने, आर एंड आर गतिविधियों, लागू परमिट प्राप्त करने, लाइसेंस आदि प्राप्त करने, परियोजनाओं के विकास, खनन/निष्कर्षण और कोयले की डिलीवरी के लिये खदान के संचालन और रखरखाव से लेकर गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरा करता है।
- इस अवसर पर सीसीएल के सीएमडी ने कहा कि कंपनी टिकाऊ खनन के माध्यम से ' आत्मनिर्भर भारत 'के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है। पिपरवार भूमिगत खदान का संचालन करते समय स्थानीय समुदाय के समग्र विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्र के लोगों के लिये हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- सीसीएल ने पिछले वित्त वर्ष में 68.6 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया था। पिपरवार क्षेत्र पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) 13.13 मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन के साथ सीसीएल के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में से एक रहा है।
- पिपरवार क्षेत्र की पिपरवार ओपनकास्ट खदान कोल इंडिया की पहली खदान थी जहाँ अत्याधुनिक सीएचपी-सीपीपी के साथ पूरी तरह से मोबाइल इन-पिट क्रशिंग और कन्वेंजेंस सिस्टम स्थापित किया गया था, जो इसे अपने आप में अनूठा बनाता है।